भोपाल में कमला पार्क मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई।

प्रशासन का दिल और अंतर्रात्मा है शासकीय कर्मचारी-मुख्यमँत्री

शासकीय कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान एवं आभार

भोपाल 15 जुलाई (ए) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासकीय कर्मचारी प्रशासन का दिलए अंतर्रात्मा और दोनों हाथ हैं। सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों के लिये निरंतर कार्य किये गये हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह ही समझा है। भविष्य में भी निरंतर कर्मचारियों के कल्याण के कार्य किये जायेंगे। शासकीय कर्मचारी और सरकार मिलकर प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनायेंगे। मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को उज्जैन में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मान एवं आभार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के विभिन्न 45 संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शासकीय कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान दिये जानेए केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महँगाई भत्ताए अध्यापक संवर्ग को शिक्षा विभाग में सम्मिलित करने तथा सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष किये जाने पर आभार व्यक्त किया है।

मध्यप्रदेश शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष रमेशचन्द्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखा है और उनके हितों की रक्षा की है। मुख्यमंत्री द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये भी कारगर कदम उठाये गये हैं।

छानबीन समिति ने पूछा 2013 में क्यों हारी थी कांग्रेस

नेताओं और टिकटार्थियों का साक्षात्कार

भोपाल 15 जुलाई (ए) विधानसभा चुनाव 2018 के लिए कांग्रेस की छानबीन समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने अपने आक्रमण तेवरों के साथ पूर्व सांसदों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और मोर्चा के प्रमुखों के साथ सीधा संवाद किया।

छानबीन समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री पूरी जानकारी के साथ ऑफिस में चुनाव के आंकड़ों को लेकर उन्होंने पूर्व सांसदों विधायकों और पदाधिकारियों से जो सवाल किए उनसे नेता हतप्रभ होकर रह गए।

छानबीन समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री और उनके साथ आए नेत्रा डिसूजा और अजरा लालू ने करीब 11 घंटे तक अलग.अलग नेताओं को बुलाकर लगातार उनसे चर्चा की। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के जाति समीकरण और प्रत्याशियों को लेकर उन से राय.शुमारी भी की।

कांग्रेस के कई पूर्व सांसद भी टिकट की दौड़ में शामिल है। छानबीन समिति के समक्ष उन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया। इस बीच संगठन के पदाधिकारियों ने महिलाओं के लिए वुवाओं के लिए अलग.अलग टिकट दिए जाने की मांग रखी। छानबीन समिति ने 24 पूर्व सांसदों को भोपाल बुलाया था। लगभग 12 सांसदों की पहले दिन छानबीन समिति के सदस्यों के साथ चर्चा हुई।

टिकट वितरण को लेकर नेताओं ने अपने सुझाव भी दिए। अधिकांश लोगों ने टिकट वितरण में कोटा या परमिट सिस्टम के स्थान पर जीतने वाले कैंडिडेट को सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कही। दो बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को टिकट नहीं देने और पत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द करने की मांग छानबीन समिति से नेताओं ने की है।

मध्यप्रदेश में 26 जन औषधि केंद्र बंद

भोपाल 15 जुलाई (ए) मध्यप्रदेश में जेनेरिक दवाओं के लिए पिछले 3 सालों में 71 जन औषधि केंद्र खोले गए थे इसमें से 26 औषधि केंद्र बंद हो गए हैं। सबसे कम जन औषधि केंद्र मध्य प्रदेश में है। उसके बाद भी बड़ी तेजी के साथ बंद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और दवा कंपनियों की मिलीभगत से जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता मध्यप्रदेश में ना के बराबर है।

2014 15 से केंद्र सरकार सभी राज्यों में जन औषधि केंद्र खोलकर मरीजों को ब्रांडेड दवाओं से आधे से कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने की नीति पर काम कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आर्थिक मदद भी दी है।

देश में उत्तर प्रदेश में 484 केरल में 319 गुजरात में 260 तमिलनाडु में 256 कर्नाटक में 242 महाराष्ट्र में 205 छत्तीसगढ़ में 194 आंध्र प्रदेश में 120 राजस्थान में 99 बिहार में 85 तेलंगाना में 75 पंजाब में 73 और मध्य प्रदेश में 71 जन औषधि केंद्र खोले गए है। मध्यप्रदेश में इनमें से भी 26 जन औषधि केंद्र बंद हो गए हैं। इस हिसाब से मध्य प्रदेश देश में सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है।

सरकार के खजाने से करोड़ों का भुगतान

मध्य प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों तथा असाध्य रोग की बीमारियों के लिए सरकार के खजाने से हर साल करोड़ों रुपया अस्पतालों को देती है। ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर अस्पताल करोड़ों रुपए की लूट सरकारी खजाने से करते हैं। इसके बाद भी मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है।

कमीशनखोरी

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का भुगतान निजी अस्पतालों को किया जा रहा है। इन अस्पतालों के बिल भुगतान में कमीशनबाजी का भारी खेल चल रहा है। ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर कमीशन की रकम भी अधिकारियों को ज्यादा मिलती है यह भी एक बड़ा कारण है कि स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय की कोई रुचि जेनेरिक दवाओं के प्रति नहीं है।

मुख्यमंत्री ने किया भगवान महाकालेश्वर का पूजन अर्चन

भोपाल 15 जुलाई (ए) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह उज्जैन में सपत्नीक महाकालेश्वर मंदिर में पूजन.अर्चन किया। मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा आयोजित आशीर्वाद समारोह में भी शामिल हुए।

आशीर्वाद समारोह का संचालन डॉ पीयूष त्रिपाठी ने किया। बटुकों द्वारा इस अवसर पर पुरुषसूक्त वाचन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बताया कि राज्य शासन द्वारा महाकाल मंदिर के लिटे महाराजवाड़ा स्कूल की 6 एकड़ जमीन दी गई है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री गौरीशंकर बिसेनए नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंहए राज्यसभा सदस्य डॉ सत्यनारायण जटियाए लोकसभा सदस्य डॉ चिंतामन मालवीय उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल एवं अन्य जन.प्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद थे।

राजधानी में जिंदाबाद मुर्दाबाद पर लगा ब्रेक

पार्क और सड़कों पर सुनाई नहीं दे रहे हैं मुर्दाबाद के नारे

भोपाल 15 जुलाई (ए) बीते एक महीने से राजधानी के पार्क और सड़कों पर मुर्दाबाद के नारे सुनाई नहीं दे रहे हैं। कर्मचारी आंदोलन के चलते शहर में जाम जैसे हालत भी नहीं बन रहे हैं। इससे राजधानी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। पूर्व में महिला अध्यापकों के सामूहिक मुंडन से लेकर अध्यापकए अतिथि विद्वानों को मिलाकर 50 से ज्यादा बड़े आंदोलन हुए। तब शहरवासियों को परेशान होना पड़ा था। महिला अध्यापकों के सामूहिक मुंडन ने सरकार को भी परेशानी में डाल दिया था। अब स्थिति बदल गई है। सरकार ने कुछ मांगों को पूरा कर कर्मचारी नेताओं को मनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ मैदानी कर्मचारी ज्यादातर मांगों को अब भी लंबित बता रहे हैं। 13 जनवरी को आजाद अध्यापक संघ की अध्यक्ष शिल्पी शिवानी के नेतृत्व में महिलाओं ने राजधानी में सामूहिक मुंडन कराया। इसके बाद सरकार पर कई आरोप लगे। इसके बाद दूसरे आंदोलन तेज हुए। फिर 2 लाख 37 हजार अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ। आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं। 2 दिसंबर को 11 मील पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता.सहायिका धरने पर बैठ गईं। 6 घंटे आवागमन बाधित रहा। लोग परेशान होते रहे। इसके बाद सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताए सहायिकाओं का वेतन बढ़ाया। अंबेडकर पार्क में अतिथि शिक्षक समेत 6 संवर्ग की सामूहिक हड़ताल हुई। 26 फरवरी को कर्मचारी नेता शुभंचरण दुबे पानी की टंकी पर चढ़ गए। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक तुलसीनगर क्षेत्र में जाम की स्थिति रही। लोग परेशान होते रहे। अब भी मांगे पूरी नहीं हुई। गेड.पे में सुधार की मांग को लेकर 16 मार्च को डिप्लोमा इंजीनियरों ने महारैली की।

टीन शेड के पास रैली के रूप में हजारों डिप्लोमा इंजीनियर जुटेए जाम लग गया। इसके बाद गेड.पे 3200 से 3600 किया। इंजीनियर गेड.पे 4200 करने की मांग पर अड़े हैं। वनकर्मियों ने मई.जून में 14 दिन काम बंद हड़ताल की। जंगल और वन्यप्राणी को नुकसान पहुंचा। इसके बाद कुछ मांगे मानी गईए लेकिन कुछ पर गतिरोध खत्म नहीं हुआ। मप्र संविदा अधिकारी.कर्मचारी महासंघ ने नियमित करने की मांग को लेकर पहले दांड़ी यात्रा कीए बाद में अंबेडकर पार्क में आंदोलन किया। इसके बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दो सप्ताह तक प्रदेश में काम बंद कर दिया। सरकार ने भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण दिया। मप्र कर्मचारी कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र खांगेल ने कहा कि दुग्ध संघ के हजारों कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं दिया गया है। छठवें वेतनमान का 63 महीने का एरियर्स भी नहीं दिया। मप्र संविदा अधिकारी.कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि 20 फीसदी पदों पर आरक्षण का लाभ संविदाकर्मियों को कब तक मिलेगाए यह तय नहीं है। क्योंकि ज्यादातर संविदाकर्मी उम्र में बाहर हो जाएंगे। मप्र कर्मचारी संघ के महामंत्री आमोद तिवारी ने कहा कि वनकर्मियों की ज्यादातर मांगे अब भी लंबित है। संयुक्त मोर्चा के जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्थाईकर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति समेत कई संवर्गों की मांगे अब भी लंबित हैं।

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमों में संशोधन

भोपाल 15 जुलाई (ए) पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत स्थापित नियमों में संशोधन किया गया है। जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी के माता.पिताध्अभिभावकों की वार्षिक आयए छात्रवृत्ति अन्तर्गत देय अनुरक्षण भत्ता की दरोंए फीस के सम्बन्ध में शासन द्वारा संशोधित निर्देश जारी किये गये हैं। जारी किये गये संशोधन नियमानुसार ऐसे नियोजित विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय उनके माता.पिताध्अभिभावकों की आय सहित तीन लाख रुपए से अधिक न होए छात्रवृत्ति अन्तर्गत देय अनुरक्षण भत्ते की दरोंए फीस के सम्बन्ध में संशोधित निर्देश जारी किये गये हैं। संशोधित नियम एवं पात्रतानुसार शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति संस्था प्रमुख स्वीकृत कर स्वीकृति की प्रति विभाग को उपलब्ध करायें एवं अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संशोधित नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रस्ताव एवं आवेदन मय दस्तावेजों के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रस्तुत करें।

श्री जगन्नाथ मंदिर में नेत्रोत्सव मना

डाबुगां 15 जुलाई (सन्यूस) डाबुगां ब्लाक मुख्यालय स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में गत 13 जुलाई को विधि विधान पूर्वक भगवान श्री जगन्नाथ के नेत्रोत्सव मनाया गया।

विदित हो कि देवस्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ हो गये थे एवं 15 दिनों तक अनसर काल पर थे एवं इसके बाद भक्तों को दर्शन दिये। इस अवसर पर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा एवं श्री जगन्नाथ को ये वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित किया गया। मंदिर के पूजक नवीन पाढ़ी के व्दारा विधि पूर्वक हवन, पूजन आदि किया। कर्ता जी. वेंकटेश्वर राव एवं उनकी धर्मपत्नी के व्दारा पूजा कार्य संपन्न किया गया।

नेत्रोत्सव के अवसर पर मंदिर संचालन कमेटी के स्थायी अध्यक्ष प्रभारी तहसीलदार नरसिंग गादवा, उपाध्यक्ष जी. वेंकेटेश्वर राव, सचिव तथा कोषाध्यक्ष जी. साई राजू, सह सचिव भगवान महांती आदि उपस्थित थे। पूजा कार्य समापन के पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया।

नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में करदाताओं ने कराया अपने प्रकरणों का निराकरण

भोपाल 15 जुलाई (ए) नेशनल लोक अदालत में नियमानुसार सम्पत्तिकर एवं जल कर ;जल उपभोक्ता प्रभारद्ध पर लगे अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ बड़ी संख्या में करदाताओं द्वारा उठाया जा रहा है और निगम के वार्डध्जोन कार्यालय एवं नागरिक सुविधा केन्द्रों पर प्रकरणों का निराकरण कराने वालों का तांता दिन भर से लगा हुआ है और समाचार लिखे जाने तक 5336 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 7 करोड़ 10 लाख रूपये से अधिक की राशि सम्पत्तिकर व जल कर के रूप में वसूल की जा चुकी है। प्रकरणों का निराकरण कराने वाले करदाताओं का निगम कार्यालयों में आने का क्रम अभी भी जारी है।

निगम आयुक्त अविनाश लवानिया सहित निगम के अपर आयुक्तगणध्उपायुक्तगण व अधिकारियों ने शहर के विभिन्न जोन एवं वार्ड कार्यालयों में जाकर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये। नेशनल लोक अदालत के दिन शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं के शिविर लगे थे जिनमें लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रकरण निराण किये गये।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा मध्यप्रदेश में नेशनल लोक अदालत आयोजित किए जाने के निर्देशों के परिपालन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश में निहित निर्देशों अनुसार नगर निगम भोपाल द्वारा शनिवार को अपने सभी वार्डध्जोन कार्यालयों व नागरिक सुविधा केन्द्रों में नेशनल लोक अदालत शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट प्रदान की जाकर सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये बकाया थी उन्हें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट देकर निरणत किया गया जबकि 50 हजार से अधिक एवं 1 लाख रुपये तक बकाया राशि पर केवल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट एवं 1 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई।

इसी प्रकार जलकर के प्रकरणों में अधिभार सहित 10 हजार रूपये तक की बकाया राशि पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है जबकि 10 हजार रूपये से अधिक 50 हजार रूपये तक की अधिभार सहित बकाया राशि पर अधिभार में 75 प्रतिशत तथा अधिभार सहित 50 हजार रूपये से अधिक की बकाया जलकर की राशि पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाकर प्रकरणों का निराकरण किया। उपरोक्त छूट केवल नेशनल लोक अदालत के आयोजन दिनांक को मात्र एक बार दी गई है।

स्वरोजगार योजना के संबंध में स्पष्टीकरण

भोपाल 15 जुलाई (ए) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आय सीमा के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकर दाता न हो, से अभिप्राय केवल आवेदक आयकर दाता न हो से है। इसी तरह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को प्राप्त जिन आवेदनों का 16 नवम्बर 2017 के पूर्व टॉस्क फोर्स कमेटी की अनुशंसा उपरांत बैंकों को अग्रेषित किया गया है, उन पर पात्रता, बैंक स्वीकृति, वितरण एवं अनुदान इत्यादि हेतु पूर्व के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा 16 नवम्बर, 2017 अथवा तत्पश्चात टॉस्क फोर्स कमेटी से अनुशंसित प्रकरणों में नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष की अनुमति से 64 साल तक विधानसभा में काम कर सकेगें अधिकारी कर्मचारी

भोपाल 15 जुलाई (ए) मध्यप्रदेश विधानसभा के कर्मचारी और अधिकारी 64 वर्ष की आयु तक विधानसभा में कार्य कर सकते हैं। यह संभव होगा यदि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवा से संतुष्ट होने पर 2 वर्ष की अवधि बढ़ा सकेंगे।

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामें और शोर.शराबे के बीच बिना चर्चा के सेवानिवृत्ति विधेयक पास हो गया है राज्य सरकार के नियम विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा की नियमावली में अधिकार हैए कि वह 2 वर्ष की समय अवधि अपने विशेषाधिकार से बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल कर दी है। ऐसी स्थिति में विधानसभा में अब अधिकारी कर्मचारी अध्यक्ष की अनुशंसा पर 2 साल अधिक काम कर सकेंगे। अर्थात 64 साल में उनकी सेवानिवृत्ति होगी।

महिला शराब तस्कर गिरफ्तार

भोपाल 15 जुलाई (ए) राजधानी के शाहजहांनाबाद इलाके में देशी शराब की तस्करी करते हुए एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से 28 हजार की देशी शराब बरामद की है। थाना पुलिस ने बताया कि बीती रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक महिला शराब तस्कर को हिरासत में लिया गया। आरोपी महिला की पहचान मुमताज बी पति अनस निवासी मदर इंडिया कालोनी के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि महिला के कब्जे से 346 देशी शराब के क्वार्टर बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए हैए जिनकी कीमत 27 हजार बताई गई है। महिला अपने घर से देशी शराब की तस्करी करने का काम कर रही थी। आरोपिया के खिलाफपुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।